†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR SAHU): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.]

ADJUSTMENTS IN PLAN

*14. SHRI SITARAM JAIPURIA
SHRI GURUDEV GUPTA:‡
SHRI M. C. SHAH:
SHRI M. M. DHARIA:
SHRI S. C. DEB:
SHRI D. THENGARI:
SHRI P. ABRAHAM:
SHRI JAGAT NARAIN:
SHRI G. MURAHARI:
SHRI RAM SINGH:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has asked the State Governments for certain adjustments in the current year's (1965-66) Plan to meet the present defence needs;

(b) if so, what are the instructions issued in this connection;

(c) the reaction of the State Governments in this matter; and

(d) whether Government are also re-considering the order of priorities of the Fourth Five Year Plan to achieve self-sufficiency in Defence and Agriculture?

THE MINISTER OF PLANNING (*SHRI B. R. BHAGAT*:): (a) to (d). I will be making a statement during the week on the reorientation of our plans in the light of the present emergency.

And I will request the hon. Member to wait till I give the fuller statement about this.

SHRI M. C. SHAH: What is the allocation made for the Fourth Plan and what proportion of it is allocated to defence and agriculture?

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, the Fourth Plan is not drawn up yet and we cannot say that at this stage.

SHRI M. C. SHAH: May I know what is the response of the State Governments to this directive of the Planning Commission and whether they have received any factual reports from the State Governments?

SHRI B. R. BHAGAT: The State Governments are falling into the line of the new priorities that we have established in view of the emergency.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : जैसा कि श्रीमान ने अभी बतलाया कि स्टेटमेंट तो बाद में देंगे, मगर कुछ स्टेट्स को इसके बारे में कुछ इन्स्ट्रक्शन्स भेजे गए है या नहीं—इसकी जानकारी क्या अभी देंगे ?

श्री बी० आर० भगत : जी, भेज दिऐ गए है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : किस आशय की भेजी है, क्या इन्स्ट्रक्शन्स दिए है ?

श्री बी० आर० भगत : एमरजेन्सी को देखते हुए, आम तौर से हमने खेती और खाद्यान्न में स्वावलम्बी बनने के लिए जो उपाय हों उन पर तेजी से कदम उठाने के लिए कहा है । दूसरी बात जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे इर्रीगेशन के या दूसरे, जिनको हम जल्दी पूरा कर सकते है, उनको पूरा करें और दूसरे प्रोजेक्ट्स जिनकी शुरुआत नही हुई है या शुरू करने वाले हैं उनको मुअत्तिल रखें । ऐसी सारी बातें कही गई हैं ।

श्री जगत नारायण : क्या वजीर साहब बतलाएंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन से दरख्वास्त की है कि हमें आगे टैक्स लगाने के लिये मजबूर न किया जाय ।

---

†[ ] English translation.

‡The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudev Gupta.

मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मजबूर किया कि टैक्स लगाएं जब कि वहां की हालत यह है कि लड़ाई की वजह से एकानामिक हालत बिगड़ गई है और लोगों का करोड़ों रुपया इस जंग में बिल्कुल एक जगह बन्द हो गया है, उससे कोई आमदनी नहीं हो सकती है, तो क्या प्लानिंग कमीशन पंजाब गवर्नमेंट को इजाजत देगी कि वह कोई टैक्स न लगाए ।

श्री बी० आर० भगत : इस बात में माननीय सदस्य को गलतफहमी हो रही है, हम तो कभी कोई मजबूर नहीं करते है कि वह टैक्स लगाएं । ऐसी कोई बात नहीं है । हम कोई मजबूर नहीं करते और जोर नहीं डालते कि वह टैक्स लगाए ।

श्री जगत नारायण : मेरे पास चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि टैक्स लगाइये । वह यह है :—

"The Ram Kishan Government is faced with a piquant situation: the Planning Commission is compelling it to raise its tax revenues but the Congress Legislature Party is unanimously opposed to this step."

श्री सभापति : आपने जो पढ़ा, उसमें है: "The situation is compelling."

श्री जगत नारायण : इसमें आगे यह है:—

"Despite a frank statement by Chief Minister Ram Kishan and some other Ministers that the taxation measures had been brought forward under heavy Central pressure, the Party refused to approve taxation Bills . . .

राम किशन जी ने वहां अपनी पार्टी में यह स्टेटमेंट किया है कि प्रेशर डाला गया कि जरूर टैक्स लगाइये । तो यह सही है या नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि प्लानिंग कमीशन खर्च का भी और आमदनी का भी एस्टीमेट बनाती है और इसके लिये स्टेट्स से पहले पूछ भी लिया जाता है । इस वास्ते प्लानिंग कमीशन का यह फर्ज है कि वह वक्त-वक्त पर स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसका याद दिलावें कि उन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने का वायदा किया था, उसे क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऐसा प्लानिंग कमीशन हमेशा करेगी और इस बार भी किया है ।

श्री बी० आर० भगत : कोई मजबूरी नहीं है ।

SHRI G. MURAHARI: The Minister said that he would make a fuller statement later, but I would like to know from him whether the answers to (a) and (d) are in the affirmative or not.

SHRI B. R. BHAGAT: We have written to the State Governments, as I said earlier also in my reply, and we will deal with these specific instructions. That is why I said that I would look into this question when I make a statement. We have written to the State Governments and also given them advice—I will not say instructions—in this matter.

SHRI S. SUPAKAR: The question of raising additional resources by the States is also related to the two difficult problems of shortfall in agricultural production this year in certain States as well as our defence needs. In that connection, did the Planning Commission insist on these great expectations from the States?

SHRI T. N. SINGH: In all such cases when situations change, the Government of India do point out to the Planning Commission that in such a situation a revised view has to be taken and whenever their attention is drawn the Planning Commission do consider the problem.